CHETANA
International Journal of Education (CIJE)

Peer Reviewed/Refereed Journal
ISSN : 2455-8279 (E)/2231-3613 (P)

Impact Factor
SJIF 2026-8.584

Prof. A.P. Sharma
Founder Editor, CIJE
(25.12.1932 - 09.01.2019)

वर्तमान समय की शैक्षिक आवश्यकताओं के संदर्भ में सर्व शिक्षा अभियान की प्रासंगिकता : एक वैचारिक अध्ययन

सुवीरा यादव
शोधार्थी
प्रो.विनोद कुमार उपाध्याय
प्राचार्य, शिक्षा संकाय
महाराजा विनायक ग्लोबल विश्वविद्यालय, जयपुर
Email: suvirayadav0255@gmail.com, Mob: 7597897887

First draft received: 18.04.2026, Reviewed: 22.04.2026
Final proof received: 15.05.2026, Accepted: 23.06.2026

शोध-सार

शिक्षा किसी भी राष्ट्र के सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक विकास का प्रमुख आधार है। भारत में प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के उद्देश्य से वर्ष 2001 में सर्व शिक्षा अभियान (SSA) प्रारंभ किया गया। इस अभियान का उद्देश्य 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के प्रत्येक बच्चे को निःशुल्क, अनिवार्य एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना, विद्यालयों तक सार्वभौमिक पहुँच सुनिश्चित करना, बालिका शिक्षा को बढ़ावा देना तथा सामाजिक एवं लैंगिक असमानताओं को कम करना था। वर्तमान समय में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, डिजिटल शिक्षा, समावेशी शिक्षा, कौशल-आधारित अधिगम, आधारभूत साक्षरता एवं संख्यात्मक ज्ञान (FLN) तथा सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) के कारण शिक्षा की आवश्यकताओं में व्यापक परिवर्तन आया है। ऐसी परिस्थितियों में सर्व शिक्षा अभियान की वर्तमान प्रासंगिकता का अध्ययन आवश्यक हो जाता है।

प्रस्तुत शोध-पत्र वैचारिक अध्ययन पर आधारित है, जिसमें पुस्तकों, शोध-पत्रों, सरकारी प्रतिवेदनों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 तथा अन्य द्वितीयक स्रोतों का विश्लेषण किया गया है। अध्ययन से स्पष्ट होता है कि यद्यपि सर्व शिक्षा अभियान को वर्तमान में समग्र शिक्षा कार्यक्रम में समाहित कर दिया गया है, फिर भी इसके मूल उद्देश्य—सभी बच्चों के लिए समान, समावेशी एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना—आज भी पूर्णतः प्रासंगिक हैं। अध्ययन यह भी इंगित करता है कि शिक्षा की गुणवत्ता, डिजिटल असमानता, शिक्षक प्रशिक्षण, आधारभूत अधिगम, समावेशी शिक्षा तथा आधुनिक तकनीक के प्रभावी उपयोग जैसे क्षेत्रों में निरंतर सुधार की आवश्यकता है। निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि वर्तमान शैक्षिक आवश्यकताओं के अनुरूप सर्व शिक्षा अभियान के मूल सिद्धांतों को सुदृढ़ करते हुए प्रभावी रूप से लागू करना गुणवत्तापूर्ण एवं समावेशी शिक्षा व्यवस्था के निर्माण के लिए अत्यंत आवश्यक है।

मुख्य शब्द : *सर्व शिक्षा अभियान, वर्तमान शैक्षिक आवश्यकताएँ, समावेशी शिक्षा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, वैचारिक अध्ययन.*

प्रस्तावना

सर्व शिक्षा अभियान सुदृढ़ शिक्षा प्रणाली के माध्यम से प्राथमिक शिक्षा को सार्वभौमिक बनाने का एक प्रयास है। यह पूरे देश में गुणवत्तापूर्ण एवं समावेशी शिक्षा की माँग का जवाब है। SSA कार्यक्रम मिशन मोड में सामुदायिक स्वामित्व वाली गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करके सबसे गरीब बच्चों को मानवीय क्षमताओं को बेहतर बनाने का अवसर प्रदान करने का भी एक प्रयास है। सर्व शिक्षा अभियान प्राथमिक शिक्षा के लिए एक समय-सीमा वाला कार्यक्रम है। यह पूरे देश में गुणवत्तापूर्ण प्राथमिक शिक्षा के माध्यम से सामाजिक न्याय को बढ़ावा मिलता है।

SSA के माध्यम से प्राथमिक विद्यालयों के प्रबंधन में पंचायती राज संस्थाओं, विद्यालय प्रबंधन समितियों, ग्राम शिक्षा समितियों, अभिभावक-शिक्षक संघों, मातृ शिक्षक संघों और जनजातीय समुदायों को उपयुक्त रूप से शामिल करने का प्रयास है।

प्रस्तुत वैचारिक अध्ययन का उद्देश्य वर्तमान समय की शैक्षिक आवश्यकताओं के संदर्भ में सर्व शिक्षा अभियान की प्रासंगिकता का विश्लेषण करना है। यह अध्ययन अभियान की उपलब्धियों, वर्तमान चुनौतियों तथा बदलते शैक्षिक परिदृश्य में इसकी उपयोगिता का विवेचन करता है। साथ ही यह अध्ययन इस बात पर भी प्रकाश डालता है कि समकालीन आवश्यकताओं के अनुरूप सर्व शिक्षा अभियान के सिद्धांतों एवं उद्देश्यों को और अधिक प्रभावी बनाकर गुणवत्तापूर्ण प्राथमिक शिक्षा के लक्ष्यों को सशक्त किया जा सकता है।

शिक्षा किसी भी राष्ट्र के सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक विकास का आधार है। यह न केवल व्यक्ति के सर्वांगीण विकास का माध्यम है बल्कि समाज में समानता, न्याय एवं सशक्तिकरण की स्थापना का भी प्रमुख साधन है। भारत सरकार ने प्रत्येक बच्चे को गुणवत्तापूर्ण प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से वर्ष 2001 में सर्व शिक्षा अभियान प्रारम्भ किया।

वर्तमान समय में शिक्षा का स्वरूप तेजी से बदल रहा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, डिजिटल शिक्षा, समावेशी शिक्षा, आधारभूत साक्षरता, कौशल आधारित अधिगम, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) जैसे नए आयाम शिक्षा की व्यवस्था को प्रभावित कर रहे हैं। इन

परिवर्तनों के कारण यह आवश्यक हो गया है कि SSA की अवधारणाओं एवं उद्देश्यों का समकालीन शैक्षिक आवश्यकताओं के संदर्भ में पुनर्मूल्यांकन किया जाए।

अध्ययन के उद्देश्य

प्रस्तुत वैचारिक अध्ययन के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित है –

सर्व शिक्षा अभियान की अवधारणा एवं उद्देश्यों का अध्ययन करना

- सार्वभौमिक पहुँच
  6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य, समावेशी शिक्षा प्रदान करना।
- सामाजिक और लैंगिक समानता
  ग्रामीण और शहरी आबादी के साथ साथ सभी पिछड़े समुदाय जो आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े हैं उनमें शिक्षा सम्बन्धी विसंगतियों को कम करना है।
  लैंगिक भेदभाव के आधार पर शिक्षा से वंचित न रहे। लड़का और लड़की को एक समान शिक्षा का अवसर प्राप्त हो।
- शिक्षा की गुणवत्ता पर ध्यान
  SSA बेहतर इन्फ्रास्ट्रक्चर, शिक्षण प्रशिक्षण और पाठ्यक्रम विकास के माध्यम से शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने पर ध्यान केन्द्रित करता है।
- छात्रों के विद्यार्थियों के नामांकन दरों में वृद्धि
  SSA का उद्देश्य विद्यार्थियों के नामांकन दरों में वृद्धि करना है। शिक्षण सामग्री और सरकारी कार्यक्रमों के माध्यम से।
- शिक्षकों को प्रशिक्षण देना
  शिक्षकों को आधुनिक समय के अनुसार शिक्षण प्रशिक्षण देना। डिजिटल और Computer का भी प्रशिक्षण देना । नई–नई शिक्षण विधियों के बारे में जानकारी देना ताकि शिक्षक विद्यार्थियों के साथ समन्वय स्थापित कर सके।
  उपयोगी और प्रासंगिक शिक्षा एक ऐसी शिक्षा प्रणाली की खोज है जो अलगाव पैदा न करें और सामुदायिक एकजुटता पर आधारित हो। इसका उद्देश्य बच्चों को अपने प्राकृतिक वातावरण के बारे में सीखने और उन्हें महारत हासिल करने का अवसर प्रदान करना है जिससे वे आध्यात्मिक और भौतिक दोनों स्तरों पर अपनी मानवीय क्षमता का पूर्ण उपयोग कर सके। यह खोज मूल्य आधारित शिक्षा की प्रक्रिया भी होनी चाहिए जो बच्चों को केवल स्वार्थ पूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति के बजाय एक दूसरे के कल्याण के लिए काम करने का अवसर प्रदान करें

वर्तमान समय की शैक्षिक आवश्यकताएओं का विश्लेषण करना

वर्तमान समय में शिक्षा का स्वरूप तीव्र गति से परिवर्तित हो रहा है। वैश्वीकरण, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, सतत विकास लक्ष्य (SDGs) तथा बदलती सामाजिक–आर्थिक परिस्थितियों के कारण शिक्षा के उद्देश्य केवल साक्षरता तक सीमित नहीं रह गए हैं। आज शिक्षा का लक्ष्य विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास, जीवन कौशल का निर्माण, नवाचार, रोजगारपरक दक्षताओं का विकास तथा उत्तरदायी नागरिक तैयार करना है। वर्तमान शैक्षिक आवश्यकताओं का विवरण निम्नलिखित है –

- गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की आवश्यकता
  आज केवल विद्यालय में नामांकन कराना पर्याप्त नहीं है, बल्कि विद्यार्थियों को ऐसी शिक्षा प्रदान करना आवश्यक है जिससे उनका बौद्धिक, सामाजिक, भावनात्मक एवं नैतिक विकास हो। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा विद्यार्थियों में आलोचनात्मक चिंतन, समस्या समाधान, रचनात्मकता तथा निर्णय लेने की क्षमता विकसित करती है।
- समावेशी शिक्षा की आवश्यकता
  वर्तमान शिक्षा व्यवस्था का उद्देश्य प्रत्येक बच्चे को बिना किसी भेदभाव के समान अवसर प्रदान करना है। दिव्यांग बच्चों, बालिकाओं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक वर्ग तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना आज की प्रमुख आवश्यकता है।
- डिजिटल एवं तकनीकी शिक्षा
  डिजिटल क्रांति के कारण शिक्षा में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का महत्व अत्यधिक बढ़ गया है। स्मार्ट कक्षाएँ, ई–लर्निंग, ऑनलाइन शिक्षा, डिजिटल पुस्तकालय, शैक्षिक ऐप तथा कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आधारित शिक्षण आज की शिक्षा का अभिन्न अंग बन चुके हैं। विद्यार्थियों और शिक्षकों दोनों के लिए डिजिटल साक्षरता आवश्यक हो गई है।
- कौशल आधारित शिक्षा
  वर्तमान समय में केवल सैद्धांतिक ज्ञान पर्याप्त नहीं है। विद्यार्थियों में संचार कौशल, नेतृत्व क्षमता, समस्या समाधान, टीमवर्क, उद्यमिता, वित्तीय साक्षरता तथा व्यावसायिक दक्षताओं का विकास भी आवश्यक है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भी कौशल आधारित शिक्षा पर विशेष बल देती है।
- आधारभूत साक्षरता एवं संख्यात्मक ज्ञान
  प्राथमिक स्तर पर पढ़ना, लिखना तथा गणना करना प्रत्येक बच्चे का बुनियादी अधिकार है। यदि प्रारंभिक कक्षाओं में ये आधारभूत दक्षताएँ विकसित नहीं होतीं, तो आगे की शिक्षा प्रभावित होती है। इसलिए प्रारंभिक शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करना अत्यंत आवश्यक है।
- मूल्यपरक एवं नैतिक शिक्षा
  आधुनिक समाज में नैतिक मूल्यों, सामाजिक उत्तरदायित्व, सहिष्णुता, ईमानदारी, अनुशासन, सहयोग तथा संवैधानिक मूल्यों का विकास शिक्षा का महत्वपूर्ण उद्देश्य है। शिक्षा केवल ज्ञान अर्जन का माध्यम नहीं, बल्कि चरित्र निर्माण का भी आधार है।
- पर्यावरण एवं सतत विकास शिक्षा
  जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण संरक्षण तथा प्राकृतिक संसाधनों के संतुलित उपयोग के प्रति जागरूकता विकसित करना आज की महत्वपूर्ण शैक्षिक आवश्यकता है। विद्यार्थियों में पर्यावरण संरक्षण एवं सतत विकास के प्रति जिम्मेदारी का भाव विकसित किया जाना आवश्यक है।
- शिक्षक दक्षता एवं सतत प्रशिक्षण
  गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए प्रशिक्षित, दक्ष एवं प्रेरित शिक्षक आवश्यक हैं। बदलती शिक्षण तकनीकों, डिजिटल साधनों तथा नवीन शिक्षण विधियों के अनुरूप शिक्षकों का नियमित प्रशिक्षण समय की आवश्यकता है।
- जीवन कौशल एवं मानसिक स्वास्थ्य
  वर्तमान प्रतिस्पर्धी वातावरण में विद्यार्थियों को तनाव प्रबंधन, आत्मविश्वास, भावनात्मक संतुलन, निर्णय क्षमता, संचार कौशल तथा सामाजिक समायोजन जैसे जीवन कौशलों का विकास करना आवश्यक है। मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता भी शिक्षा का महत्वपूर्ण भाग बन चुकी है।
- रोजगारोन्मुख एवं उद्यमशील शिक्षा
  वर्तमान शिक्षा का उद्देश्य विद्यार्थियों को केवल परीक्षा के लिए तैयार करना नहीं, बल्कि उन्हें रोजगार, स्वरोजगार एवं उद्यमिता के लिए सक्षम बनाना भी है। व्यावसायिक

शिक्षा एवं कौशल विकास इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

- राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप शिक्षा
  राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 बहुविषयक शिक्षा, अनुभवात्मक अधिगम, मातृभाषा में शिक्षण, लचीले पाठ्यक्रम, सतत मूल्यांकन तथा तकनीक आधारित शिक्षा पर बल देती है। इसलिए वर्तमान शिक्षा व्यवस्था को इन उद्देश्यों के अनुरूप विकसित करना आवश्यक है।
- समान अवसर एवं सामाजिक न्याय
  शिक्षा का उद्देश्य प्रत्येक बच्चे को समान अवसर प्रदान करना तथा सामाजिक, आर्थिक एवं लैंगिक असमानताओं को कम करना है। शिक्षा के माध्यम से सामाजिक न्याय, समानता एवं लोकतांत्रिक मूल्यों को सुदृढ़ किया जा सकता है।

वर्तमान शैक्षिक आवश्यकताओं के सन्दर्भ में सर्व शिक्षा अभियान की प्रासंगिकता का अध्ययन करना

भारत में सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य प्रत्येक बालक एवं बालिका को निःशुल्क, अनिवार्य एवं गुणवत्तापूर्ण प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराना था। यद्यपि वर्तमान में इस अभियान को समग्र शिक्षा कार्यक्रम में समाहित कर दिया गया है, फिर भी इसके मूल उद्देश्य आज भी भारतीय शिक्षा व्यवस्था के लिए अत्यंत प्रासंगिक हैं। बदलते सामाजिक, आर्थिक एवं तकनीकी परिवेश में सर्व शिक्षा अभियान की प्रासंगिकता निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर स्पष्ट की जा सकती है –

- शिक्षा के सार्वभौमिकरण में योगदान
  सर्व शिक्षा अभियान ने प्रत्येक बच्चे तक शिक्षा पहुँचाने के लक्ष्य को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आज भी यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि कोई भी बच्चा आर्थिक, सामाजिक, लैंगिक या भौगोलिक कारणों से शिक्षा से वंचित न रहे। वर्तमान समय में भी विद्यालय से बाहर रहने वाले बच्चों को मुख्यधारा से जोड़ने की आवश्यकता बनी हुई है।
- समावेशी शिक्षा को बढ़ावा
  वर्तमान शिक्षा व्यवस्था में समावेशी शिक्षा (Inclusive Education) को विशेष महत्व दिया जा रहा है। सर्व शिक्षा अभियान ने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग तथा दिव्यांग बच्चों को शिक्षा से जोड़ने के लिए विशेष प्रयास किए। आज भी समान अवसर उपलब्ध कराना शिक्षा व्यवस्था का प्रमुख उद्देश्य है।
- बालिका शिक्षा की निरंतर आवश्यकता
  सर्व शिक्षा अभियान के माध्यम से बालिकाओं के नामांकन एवं विद्यालय में उनकी उपस्थिति में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। वर्तमान समय में भी बालिका शिक्षा महिला सशक्तिकरण, लैंगिक समानता तथा सामाजिक विकास की आधारशिला है। इसलिए अभियान के उद्देश्य आज भी प्रासंगिक बने हुए हैं।
- गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की आवश्यकता
  आज केवल विद्यालय में प्रवेश दिलाना पर्याप्त नहीं है, बल्कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना भी आवश्यक है। सर्व शिक्षा अभियान ने शिक्षकों के प्रशिक्षण, शिक्षण सामग्री की उपलब्धता तथा विद्यालयी सुविधाओं के विकास पर बल दिया। वर्तमान समय में अधिगम परिणामों में सुधार, रचनात्मक शिक्षण तथा अनुभवात्मक अधिगम पर विशेष ध्यान देना आवश्यक है।
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के संदर्भ में प्रासंगिकता
  राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 सभी बच्चों के लिए समान, गुणवत्तापूर्ण एवं समावेशी शिक्षा पर बल देती है। सर्व शिक्षा अभियान के अनेक उद्देश्य—जैसे शिक्षा तक सार्वभौमिक पहुँच, समान अवसर, आधारभूत साक्षरता एवं संख्यात्मक ज्ञान—राष्ट्रीय शिक्षा नीति के लक्ष्यों के अनुरूप हैं। इसलिए इसकी अवधारणा आज भी महत्वपूर्ण बनी हुई है।
- डिजिटल शिक्षा के विकास में उपयोगिता
  कोविड-19 महामारी के बाद डिजिटल शिक्षा का महत्व अत्यधिक बढ़ गया है। वर्तमान समय में ऑनलाइन शिक्षण, स्मार्ट कक्षाएँ, ई-सामग्री एवं डिजिटल संसाधनों का उपयोग बढ़ रहा है। सर्व शिक्षा अभियान की मूल भावना—सभी तक शिक्षा पहुँचाना—डिजिटल माध्यमों के विस्तार के साथ और अधिक प्रभावी बन सकती है।
- सामाजिक समानता एवं न्याय की स्थापना :-
  शिक्षा सामाजिक परिवर्तन का प्रभावी माध्यम है। सर्व शिक्षा अभियान ने सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के बच्चों को शिक्षा से जोड़कर समान अवसर प्रदान करने का प्रयास किया। वर्तमान समय में भी सामाजिक न्याय एवं समानता स्थापित करने के लिए इसकी प्रासंगिकता बनी हुई है।
- विद्यालयी आधारभूत संरचना का विकास
  सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत विद्यालय भवन, अतिरिक्त कक्ष, शौचालय, पेयजल, पुस्तकालय तथा अन्य आधारभूत सुविधाओं का विकास किया गया। आज भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए सुरक्षित, स्वच्छ एवं संसाधनयुक्त विद्यालय आवश्यक हैं। विशेष रूप से ग्रामीण एवं दूरस्थ क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं का सुदृढ़ीकरण अभी भी एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है।
- शिक्षक प्रशिक्षण एवं क्षमता विकास
  किसी भी शिक्षा व्यवस्था की सफलता योग्य एवं प्रशिक्षित शिक्षकों पर निर्भर करती है। सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत शिक्षकों के प्रशिक्षण एवं व्यावसायिक विकास पर बल दिया गया। वर्तमान समय में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, नवाचार आधारित शिक्षण तथा दक्षता-आधारित शिक्षा के लिए शिक्षकों का सतत प्रशिक्षण आवश्यक है।
- सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) की प्राप्ति में योगदान
  संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य-4 (SDG-4) का उद्देश्य सभी के लिए समावेशी एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना है। सर्व शिक्षा अभियान के उद्देश्य भी इसी दिशा में कार्य करते हैं। इसलिए यह अभियान वैश्विक शैक्षिक लक्ष्यों की प्राप्ति में भी महत्वपूर्ण आधार प्रदान करता है।
- ड्रॉपआउट दर में कमी
  आज भी कुछ क्षेत्रों में आर्थिक, सामाजिक एवं पारिवारिक कारणों से विद्यार्थी विद्यालय छोड़ देते हैं। सर्व शिक्षा अभियान की रणनीतियाँ बच्चों को विद्यालय से जोड़ने तथा उनकी निरंतर उपस्थिति सुनिश्चित करने में सहायक रही हैं। इसलिए इसकी उपयोगिता आज भी बनी हुई है।
- कौशल एवं जीवनोपयोगी शिक्षा की दिशा में आधार
  वर्तमान समय में शिक्षा का उद्देश्य केवल साक्षरता तक सीमित नहीं है, बल्कि विद्यार्थियों में समस्या-समाधान, संचार, सहयोग, रचनात्मकता एवं जीवन कौशल का विकास करना भी है। सर्व शिक्षा अभियान ने विद्यालयी शिक्षा को सुदृढ़ करने का आधार तैयार किया, जिस पर कौशल आधारित एवं भविष्य उन्मुख शिक्षा का विकास संभव हुआ है।

सर्व शिक्षा अभियान के समक्ष वर्तमान चुनौतियों का विश्लेषण करना

यद्यपि सर्व शिक्षा अभियान ने प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण, नामांकन में वृद्धि तथा विद्यालयी आधारभूत संरचना के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, फिर भी वर्तमान समय की बदलती शैक्षिक परिस्थितियों में इसके समक्ष अनेक चुनौतियाँ विद्यमान हैं। इन चुनौतियों का समाधान किए बिना गुणवत्तापूर्ण एवं समावेशी शिक्षा के लक्ष्य को पूर्ण रूप से प्राप्त करना कठिन है।

- शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार की चुनौती
  वर्तमान समय में केवल विद्यालयों में बच्चों का नामांकन पर्याप्त नहीं है, बल्कि उन्हें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना भी आवश्यक है। अनेक विद्यालयों में विद्यार्थियों का अधिगम स्तर अपेक्षित मानकों से कम है। पढ़ने, लिखने तथा गणना करने जैसी आधारभूत दक्षताओं में भी कई विद्यार्थियों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।
- डिजिटल असमानता
  सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के बढ़ते उपयोग के बावजूद ग्रामीण एवं दूरस्थ क्षेत्रों में इंटरनेट, कंप्यूटर, स्मार्ट उपकरण तथा डिजिटल संसाधनों की कमी है। इससे सभी विद्यार्थियों को समान डिजिटल शिक्षा उपलब्ध नहीं हो पाती।
- प्रशिक्षित एवं दक्ष शिक्षकों की कमी
  कई विद्यालयों में योग्य एवं विषय विशेषज्ञ शिक्षकों की कमी है। साथ ही बदलती शिक्षण तकनीकों, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) तथा डिजिटल शिक्षण विधियों के अनुरूप शिक्षकों का नियमित प्रशिक्षण भी आवश्यक है। प्रशिक्षित शिक्षकों के अभाव में गुणवत्तापूर्ण शिक्षण प्रभावित होता है।
- विद्यालय छोड़ने (ड्रॉपआउट) की समस्या
  आर्थिक कठिनाइयों, पारिवारिक परिस्थितियों, बाल श्रम, बाल विवाह तथा सामाजिक कारणों से अनेक विद्यार्थी बीच में ही विद्यालय छोड़ देते हैं। विशेषकर ग्रामीण एवं पिछड़े क्षेत्रों में यह समस्या अभी भी गंभीर है।
- समावेशी शिक्षा का प्रभावी क्रियान्वयन
  दिव्यांग बच्चों, सामाजिक एवं आर्थिक रूप से वंचित वर्गों तथा दूरस्थ क्षेत्रों के विद्यार्थियों को समान एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना अभी भी एकचुनौती है। सभी विद्यालयों में आवश्यक संसाधन एवं प्रशिक्षित विशेष शिक्षक उपलब्ध नहीं हैं।
- आधारभूत संरचना की कमी
  यद्यपि सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत विद्यालयों का विकास हुआ है, फिर भी अनेक विद्यालयों में पर्याप्त कक्षाएँ, पुस्तकालय, प्रयोगशालाएँ, खेल सामग्री, स्वच्छ पेयजल, शौचालय तथा बिजली जैसी मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। इससे शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया प्रभावित होती है।
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप परिवर्तन
  राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 अनुभवात्मक अधिगम, कौशल विकास, बहुभाषिकता तथा तकनीक आधारित शिक्षा पर बल देती है। इन उद्देश्यों के अनुरूप विद्यालयों, शिक्षकों एवं शिक्षण पद्धतियों में आवश्यक परिवर्तन करना एक महत्वपूर्ण चुनौती है।
- वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता
  शिक्षा के क्षेत्र में योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए पर्याप्त वित्तीय संसाधनों की आवश्यकता होती है। कई बार बजट की कमी के कारण विद्यालयों के विकास, शिक्षक प्रशिक्षण तथा डिजिटल संसाधनों की उपलब्धता प्रभावित होती है।
- अभिभावकों एवं समुदाय की सीमित सहभागिता
  विद्यालय की गुणवत्ता में अभिभावकों एवं स्थानीय समुदाय की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अनेक क्षेत्रों में शिक्षा के प्रति जागरूकता तथा सामुदायिक सहभागिता अपेक्षित स्तर पर नहीं है, जिससे विद्यार्थियों की नियमित उपस्थिति एवं सीखने की प्रक्रिया प्रभावित होती है।
- अधिगम परिणामों का प्रभावी मूल्यांकन
  वर्तमान समय में केवल परीक्षा परिणामों के आधार पर शिक्षा की गुणवत्ता का आकलन पर्याप्त नहीं है। विद्यार्थियों के वास्तविक अधिगम, कौशल, रचनात्मकता तथा समस्या-समाधान क्षमता का समग्र मूल्यांकन करना अभी भी एक चुनौती बना हुआ है।
- सामाजिक एवं आर्थिक असमानताएँ
  गरीबी, लैंगिक भेदभाव, क्षेत्रीय असमानता तथा सामाजिक विषमताएँ आज भी अनेक बच्चों की शिक्षा में बाधा बनती हैं। इन कारणों से सभी बच्चों को समान शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराना कठिन हो जाता है।
- बदलती तकनीक एवं भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप शिक्षा
  कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), रोबोटिक्स, डेटा विज्ञान तथा अन्य उभरती प्रौद्योगिकियों के युग में शिक्षा व्यवस्था को निरंतर अद्यतन करना आवश्यक है। पाठ्यक्रम, शिक्षण विधियों एवं संसाधनों को समयानुकूल बनाना वर्तमान की महत्वपूर्ण चुनौती है।

सर्व शिक्षा अभियान को अधिक प्रभावी बनाने हेतु सुझाव प्रस्तुत करना

सर्व शिक्षा अभियान की प्रभावशीलता को बढ़ाने तथा वर्तमान शैक्षिक आवश्यकताओं के अनुरूप इसे अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए निम्नलिखित सुझाव प्रस्तुत किए जा सकते हैं –

- प्रत्येक बच्चे को गुणवत्तापूर्ण एवं समान शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए विद्यालयों में आवश्यक शैक्षिक संसाधनों की पर्याप्त व्यवस्था की जाए।
- आधारभूत साक्षरता एवं संख्यात्मक ज्ञान (Foundational Literacy and Numeracy) को प्राथमिक स्तर पर सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए।
- डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु सभी विद्यालयों में इंटरनेट, स्मार्ट कक्षाएँ,
- कंप्यूटर, प्रोजेक्टर तथा डिजिटल शिक्षण सामग्री उपलब्ध कराई जाए।
- शिक्षकों के लिए नियमित सेवाकालीन प्रशिक्षण, डिजिटल दक्षता प्रशिक्षण तथा नवीन शिक्षण विधियों पर कार्यशालाओं का आयोजन किया जाए।
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के उद्देश्यों के अनुरूप अनुभवात्मक, कौशल-आधारित एवं विद्यार्थी-केंद्रित शिक्षण को प्रोत्साहित किया जाए।
- विद्यालय छोड़ने वाले (ड्रॉपआउट) बच्चों की पहचान कर उन्हें पुनः विद्यालय से जोड़ने के लिए विशेष अभियान चलाए जाएँ।
- बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए छात्रवृत्ति, सुरक्षित विद्यालय वातावरण, परिवहन सुविधा तथा जागरूकता कार्यक्रमों का विस्तार किया जाए।
- दिव्यांग एवं विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए समावेशी शिक्षा की व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाया जाए तथा आवश्यक सहायक उपकरण उपलब्ध कराए जाएँ।
- ग्रामीण एवं दूरस्थ क्षेत्रों के विद्यालयों में आधारभूत सुविधाओं—जैसे स्वच्छ पेयजल, शौचालय, बिजली,

पुस्तकालय, प्रयोगशाला एवं खेल सामग्री—का विकास किया जाए।

- विद्यार्थियों में जीवन कौशल, नैतिक मूल्य, पर्यावरण संरक्षण, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता के प्रति जागरूकता विकसित करने वाले कार्यक्रम नियमित रूप से आयोजित किए जाएँ।
- विद्यालय प्रबंधन समितियों (SMC) को अधिक सक्रिय बनाया जाए तथा अभिभावकों एवं स्थानीय समुदाय की सहभागिता सुनिश्चित की जाए।
- विद्यार्थियों के अधिगम स्तर का नियमित एवं व्यापक मूल्यांकन किया जाए तथा कमजोर विद्यार्थियों के लिए विशेष शैक्षणिक सहायता प्रदान की जाए।
- आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति, निःशुल्क पाठ्य सामग्री, वर्दी तथा अन्य आवश्यक सुविधाओं का विस्तार किया जाए।
- स्थानीय भाषा एवं मातृभाषा में प्रारंभिक शिक्षा को प्रोत्साहित किया जाए, जिससे बच्चों का अधिगम अधिक प्रभावी हो सके।
- विद्यालयों में खेल, कला, संगीत, योग तथा सह-शैक्षिक गतिविधियों को शिक्षा का अभिन्न अंग बनाया जाए।
- शिक्षा में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), ई-लर्निंग, वर्चुअल लैब तथा अन्य आधुनिक तकनीकों का सुरक्षित एवं प्रभावी उपयोग बढ़ाया जाए।
- शिक्षा योजनाओं के लिए पर्याप्त वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराए जाएँ तथा उनके उपयोग में पारदर्शिता एवं जवाबदेही सुनिश्चित की जाए।
- समय-समय पर स्वतंत्र एजेंसियों द्वारा योजनाओं का मूल्यांकन कर प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर आवश्यक सुधार किए जाएँ।
- सामाजिक एवं लैंगिक असमानताओं को कम करने के लिए विशेष जागरूकता अभियान तथा समुदाय-आधारित कार्यक्रम संचालित किए जाएँ।
- शिक्षा को सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) तथा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप अधिक समावेशी, गुणवत्तापूर्ण, रोजगारोन्मुख एवं तकनीक-संपन्न बनाया जाए।

साहित्य समीक्षा

प्रस्तुत अध्ययन के लिए सर्व शिक्षा अभियान, शिक्षा का अधिकार अधिनियम (2009), राष्ट्रीय शिक्षा नीति (2020), शिक्षा मंत्रालय, एनसीईआरटी, यूनेस्को तथा विभिन्न शोध-पत्रों, पुस्तकों एवं सरकारी प्रतिवेदनों का अध्ययन किया गया। उपलब्ध साहित्य से ज्ञात होता है कि सर्व शिक्षा अभियान ने प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण, विद्यालयों में नामांकन वृद्धि, बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन, सामाजिक एवं लैंगिक समानता तथा विद्यालयी आधारभूत सुविधाओं के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। विभिन्न अध्ययनों में यह भी उल्लेख किया गया है कि शिक्षा की गुणवत्ता, शिक्षक प्रशिक्षण, डिजिटल शिक्षा, समावेशी शिक्षा तथा अधिगम परिणामों में सुधार की आवश्यकता अभी भी बनी हुई है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 गुणवत्तापूर्ण, समावेशी एवं कौशल-आधारित शिक्षा पर बल देती है, जो सर्व शिक्षा अभियान के मूल उद्देश्यों के अनुरूप है। उपलब्ध साहित्य के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि वर्तमान शैक्षिक आवश्यकताओं के संदर्भ में सर्व शिक्षा अभियान की प्रासंगिकता आज भी बनी हुई है तथा इस विषय पर वैचारिक अध्ययन की आवश्यकता है।

निष्कर्ष

प्रस्तुत वैचारिक अध्ययन से स्पष्ट होता है कि सर्व शिक्षा अभियान भारतीय शिक्षा व्यवस्था की एक महत्वपूर्ण एवं प्रभावी पहल रही है। इस अभियान ने प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण, विद्यालयों तक पहुँच बढ़ाने, बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन देने, सामाजिक एवं लैंगिक असमानताओं को कम करने तथा विद्यालयी आधारभूत संरचना के विकास में उल्लेखनीय योगदान दिया। वर्तमान समय में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, डिजिटल शिक्षा, समावेशी शिक्षा, कौशल-आधारित अधिगम तथा सतत विकास लक्ष्यों के कारण शिक्षा की आवश्यकताएँ बदल गई हैं। ऐसी परिस्थितियों में सर्व शिक्षा अभियान के मूल उद्देश्य आज भी अत्यंत प्रासंगिक हैं।

अध्ययन से यह भी स्पष्ट होता है कि शिक्षा की गुणवत्ता, डिजिटल असमानता, प्रशिक्षित शिक्षकों की उपलब्धता, अधिगम परिणामों में सुधार तथा समावेशी शिक्षा जैसे क्षेत्रों में निरंतर प्रयास आवश्यक हैं। सर्व शिक्षा अभियान के मूल सिद्धांतों को वर्तमान शैक्षिक आवश्यकताओं एवं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के उद्देश्यों के साथ समन्वित कर प्रभावी रूप से लागू किया जाए, तो सभी बच्चों को समान, गुणवत्तापूर्ण एवं समावेशी शिक्षा उपलब्ध कराई जा सकती है। अतः कहा

जा सकता है कि बदलते शैक्षिक परिदृश्य में सर्व शिक्षा अभियान की प्रासंगिकता आज भी बनी

हुई है तथा इसके उद्देश्यों को समयानुकूल सुदृढ़ करना भारतीय शिक्षा व्यवस्था के सतत विकास के लिए आवश्यक है।

सन्दर्भ सूची

1. भारत सरकार. (2001). सर्व शिक्षा अभियान: रूपरेखा एवं कार्यान्वयन दिशा-निर्देश. शिक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली।
2. भारत सरकार. (2009). बच्चों का निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009. शिक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली।
3. भारत सरकार. (2020). राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020. शिक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली।
4. NCERT. (2005). राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा (NCF-2005). राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, नई दिल्ली
5. UNESCO. (2020). Global Education Monitoring Report 2020: Inclusion and Education – All Means All. Paris: UNESCO.
6. Aggarwal, J. C. (2021). Theory and Principles of Education. Vikas Publishing House, New Delhi.
7. Bhatnagar, R. P., & Aggarwal, V. (2018). Educational Administration and Management. R. Lall Book Depot, Meerut.
8. मिश्रा आर.सी. (2016), प्रभावी शिक्षण एवं शिक्षक दक्षता, नई दिल्ली, एपी एच पब्लिशिंग।
9. MHRD. (2018). Educational Statistics at a Glance. Ministry of Human Resource Development, Government of India.